सैटेलाइट से होगी नागरिक सुविधाओं की मॉनिटरिंग

पटना| हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य सरकार अब सैटेलाइट के माध्यम से नागरिक सुविधाओं की मॉनिटरिंग करेगी। इसके लिए नगर विकास और आवास विभाग ने अपने स्तर से न केवल तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि कई प्रोजेक्ट पर काम भी प्रारंभ हो गया है। इसके लिए जीआईसी एवं सैटेलाइट इमर्जी का उपयोग कर शहरों का डिजिटल मैप तैयार किया जा रहा है।

इस मैप में शहर की हर चीज की जानकारी होगी। सैटेलाइट मैप में जो जानकारी दी जाएगी, वह फील्ड सर्वेक्षण से उसका मिलान कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी मैप के आधार पर नागरिक सुविधाओं से संबंधित चीजों पर नजर रखी जाएगी। यही नहीं, इसके माध्यम से नगर निकाय की सीमा और वार्डों की स्थिति के आकलन में सुविधा होगी।

डिजिटल मैप में क्या-क्या

नगर निकाय सीमा, वार्डों की स्थिति, कॉलोनियां व उसकी सीमा, टैक्स जोन, ड्रेनेज नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क, जलापूर्ति नेटवर्क, रोड व गली तथा उनका वर्गीकरण, कैरिज वे, राइट ऑफ वे, रेलवे लाइन, नदियां, नहर, तालाब, कुआं, चापाकल, नलकूप, हाईटेंशन बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे, जल मीनार, सेलफोन टावर, वाटर पंपिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, कचरा संग्रहण केंद्र, दमकल स्टेशन, बिल्डिंग फुटप्रिंट, विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग), स्ट्रीट लाइट, वाल्व, हाईड्रन्ट, पब्लिक टेप, स्लम कॉलोनी।

क्या-क्या होगा

इस मैप के जरिये शहर की नागरिक सुविधा से जुड़ी सभी चीजों पर नजर रखी जाएगी। कहां सीवरेज में परेशानी है या कहां पेयजलापूर्ति में दिक्कतें आ रही है। या, फिर कहां कचरा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। इसी तरह अन्य चीजों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी।

एक किमी पर बेंच मार्क

प्रत्येक नगर निकाय में ऑटो लेवल सर्वेक्षण के द्वारा आधे मीटर के अंतराल पर कांटूर भी बनाया जाएगा और हर एक किमी पर परमानेंट बेंच मार्क स्थापित किया जाएगा। इसका उपयोग भविष्य में ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति नेटवर्क एवं सड़क, फुटपाथ स्थापित करने और उन पर नजर रखने में होगा।

नगर आवास व विकास मंत्री बोले

इसका उद्देश्य आम लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एक वर्ष में यह परियोजना को धरातल पर लाई जाएगी। इससे न केवल लोगों को सुविधा होगी, बल्कि सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। डॉ. प्रेम कुमार

भूमि के उपयोग का भी सर्वे

सैटेलाइट के सहयोग से ही सभी शहरों में भूमि के उपयोग का सर्वेक्षण भी होगा। इससे संबंधित मकान या भूमि के उपयोग की विस्तृत जानकारी डिजिटल मैप में रहेगी।